AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

भारत में वैश्वीकरण की दिशा में किये गये आर्थिक समायोजन का अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Author
दिनेश कुमार कुम्हार
सहायक आचार्य इतिहास
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
कोटपूतली, जयपुर, राजस्थान, भारत

शोध सार

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रारम्भ के बारे में यदि विचार किया जाये तो कुछ निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता। यदि प्राचीन भारतीय परम्पराओं में जाये तो सम्पूर्ण वसुधा को एक कुटुम्ब माना गया है। 19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद ही प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बना। इसी समय रूस में समाजवादी क्रांति हुई जिसे साम्यवाद की पूर्व अवस्था माना गया। सम्पूर्ण विश्व को समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत लाकर साम्यवादी विश्व समाज की स्थापना का स्वप्न साम्यवादी विचारधारा के समर्थक देखने लगे। इन्होंने सम्पूर्ण विश्व को एक वर्गहीन व राज्य विहीन व्यवस्था के अन्तर्गत एकताबद्ध करने की परिकल्पना की। इस प्रकार समाजवादी क्रांति ने भिन्न तरीके से वैश्वीकरण का विचार उत्पन्न किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् साम्यवादी विचारधारा का तीव्र प्रसार हुआ तथा साम्यवादी क्रांति रूप में ज्ञान की परिणिति हुई। 20 वीं सदी के पूवार्द्ध तक लगभग 1/3 विश्व लाल झण्डे के नीचे आ गया। 1945 के बाद विश्व उपनिवेशवादी व साम्राज्यवादी व्यवस्था में परिवर्तित होने लगा। नव साम्राज्यवादियों के नेता के रूप में अमेरिका का उदय हुआ। दो विरोधी विचारधाराओं, समाजवाद व नव साम्राज्यवाद के मध्य अन्तर्विरोध था तथा दोनों ही एक दूसरे के अस्तित्व को चुनौती दे रहे थे। रूस एक विचाराधारा का मुखिया था, तो अमेरिका दूसरी विचारधारा का। 1962 के बाद चीन व रूस में मतभेद हुए व समाजवादी आन्दोलन दो धड़ों में बँट गया, फिर भी रूस को ही साम्यवादी आन्दोलन का मुखिया माना गया। 1980 के बाद से ही सोवियत संघ विरोधी शक्तियाँ सक्रिय गई व सोवियत रूस का विघटन प्रारम्भ हो गया। समाजवाद बिखरने लगा, पूँजीवादी प्रवृत्तियाँ पकड़ने लगीं तथा सोवियत रूस, जो विश्व समुदाय में एक मजबूत ध्रुव के रूप में खड़ा था ढह गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दो ध्रुवीय संसार अस्तित्व में आया था वह अब एक ध्रुवीय हो गया।

मुख्य शब्द

वैश्वीकरण, उद्योग, आर्थिक, पूंजी.

प्रस्तावना

वैश्वीकरण की ऐतिहासिक पाष्ठभूमि

यह शब्द अंग्रेजी के ग्लोबलाइजेशन से निकला है। ग्लोबलाइजेशन को भूमण्डलीकरण व वैश्वीकरण नामों से भी जाना जाता है। ग्लोबलाइजेशन का तात्पर्य पृथ्वी को समझाने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले ग्लोब से है। प्रतीकात्मक रूप में यह बताने का प्रयास इस शब्द के माध्यम से किया गया है कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास

ने दुनिया की दूरी कम करके सम्पूर्ण विश्व को एक ग्लोब के रूप में एकताबद्ध कर दिया है। यदि वैश्वीकरण, सम्पूर्ण विविधताओं को समाप्त कर समानता के आधार पर सम्पूर्ण विश्व को एक सद्भावनापूर्ण बिरादरी में परिवर्तित कर सके तो इसे विश्व कल्याणकारी प्रक्रिया कहा जा सकता है।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारत में वैश्वीकरण की दिशा में किये गये आर्थिक समायोजन का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करना हैः

- भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करना।
- भारत में वैश्वीकरण की समस्याओं का अध्ययन करना।
- भारत में वैश्वीकरण की दिशा में किये गये प्रयासों का अध्ययन करना।
- भारत में वैश्वीकरण की दिशा में किये गये आर्थिक समायोजन का अध्ययन करना।

शोध विधि व उपकरण

इस शोध पत्र से संबंधित तथ्यों एवं सूचनाओं को एकत्रित करने में पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं के लेखो, समाचार पत्रों, शोध प्रबंधों के माध्यम से द्वितीयक स्त्रोत सामग्री प्राप्त की गयी।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँः ये कम्पनियाँ अनेक राष्ट्रों की पूँजी व प्रौद्योगिकी से कार्यरत हो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन व व्यापार का कार्य करती हैं। प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी स्थापना के समय से ही वैश्वीकरण व अन्तर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित कर रहा है। इसने अपने विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से विश्व स्तर पर विभिन्न नीतियों व व्यवस्थाओं में एकरूपता स्थापित कर वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँः अनेक अन्तर्राष्ट्रीय तथा विश्वव्यापी समस्याऐं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के समक्ष चुनौती के रूप में उपस्थित हुई हैं। इनका स्वरूप भी सार्वभौमिक हो गया जैसे आतंकवाद , मादक व नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार आदि। इनसे निपटने के लिए किये गये प्रयासों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया है।

क्षेत्रीय संगठनः 20 वी सदी के सातवें दशक में क्षेत्रीय सहयोग संगठनों की स्थापना प्रारम्भ हुई। इसमें यूरोपीय संघ सबसे प्रभावी माना जा सकता है। ऐसे ही ओपेक, एपेक, एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन आदि, और ऐसे देश जब गुट बनाते हो, तो आपस में बहुत समीप आते हैं, व इससे भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बल मिलता है।

1948 में जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भारत में अपनायी गयी, उसमें राष्ट्रवाद और स्वतन्त्रता आन्दोलन के मूल्य समाहित थे और आत्मनिर्भरता के तत्व पर विशेष बल दिया गया। तत्पश्चात् समाजवादी समाज की स्थापना के लिए निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था में स्थान दिया गया व मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, पर उसमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि विदेशी पूँजी व प्रौद्योगिकी ने भारत को दो सदियों तक दास बनाकर रखा। अतः इस मुद्दे पर विशेष सावधानी बरती जाये व अति आवश्यकता होने पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ही इनके प्रवेश को सीमित रखा जाऐ। 70 का दशक भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीयकरण का युग था। 80 का दशक उदारीकरण का युग माना जाता है। 1991 के बाद से ही वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, अर्थात् उदारीकरण ने ही वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किया।

वैश्वीकरण के अन्तर्गतः विदेशी कम्पनियों को आर्थिक क्षेत्र निवेश की अनुमति दी गयी, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोला गया व बहुराष्ट्रीय निगमों व बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को आकर्षित कर निवेश को बढ़ावा दिया गया। आयात–निर्यात में मात्रात्मक प्रतिबन्धों व प्रशुल्कों को कम किया गया। निर्यात प्रोत्साहन हेतु अनेक प्रकार की रियायतें दी गई, जैसे शुल्क माफी भारतीय कम्पनियों को विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग की अनुमति

दी गयी। विदेशी प्रौद्योगिकी को खुला प्रवेश देना। विदेशी विनिमय नियंत्रक कानूनों को धीरे–धीरे समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। भारत में वैश्वीकरण के सक्रिय प्रभाव 1965 से प्रारम्भ होते हैं, जब विदेशी पूँजी व तकनीकी अनेक रियायतें दी गयी व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उन क्षेत्रों में भी काम करने की अनुमति दी गई, जिनमें उन्हें पहले काम करने की अनुमति नहीं थी। विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम के प्रावधानों में रियायत देने का कार्य आरम्भ हुआ। 1990–91 को भारतीय आर्थिक परिस्थितियों में विश्व बैंक के दबाव में आकर भारत को वैश्वीकरण की नीति अपनानी पड़ी। इसी क्रम में डंकल प्रस्तावों पर सहमति प्रदान करते हुए अप्रैल 1994 में भारत ने गैट समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया फिर 1 जनवरी 1995 को गठित विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता भी भारत ने स्वीकार कर ली। वैश्वीकरण के तहत भारत, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हो गया है और अपनी सम्पूर्ण अवधारणाओं मान्यताओं व राष्ट्रीय मूल्यों में लोच लाकर अर्थव्यवस्था में अनेक संरचनात्मक समायोजन कर रहा है।

व्याख्या एवं विश्लेषण

औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य सुधार

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कई उद्योगों में 51 प्रतिशत तक अंश पूँजी की छूट और उसके लिए स्वचालित अनुमोदन की व्यवस्था से उन्हें भारतीय उद्योगों में अपनी नीति निर्धारण का अधिकार मिल गया है। इससे जहाँ एक ओर उन्नत तकनीकी के मुक्त आयात का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वहाँ दूसरी ओर भारत में अधिकाधिक निवेश का आकर्षण पैदा हुआ है। 1996–97 में 48 उद्योगों तक फैला दिया गया है।

अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों में विदेशी पूँजी निवेश को उदार बनाने से देश में 1991–2005 की अवधि में लगभग 250062 हजार करोड़ रुपये तुल्य विदेशी पूँजी निवेशों के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं व 131385 करोड़ रुपये तुल्य विदेशी पूँजी निवेश का प्रवाह हुआ है। विदेशी पूँजी निवेश के प्रस्तावित अनुमोदनों में 2004–05 तक निवेश, दूरसंचार क्षेत्र में 41371 करोड़ रुपये तुल्य है, जबकि ईंधन क्षेत्र के लिए सर्वाधिक 43667 करोड़ रुपये, धात्विक उद्योगों के लिए 15442 करोड़ रुपये, परिवहन उद्योगों के लिए 21110 करोड़ रुपये व उपभोग क्षेत्र के लिए 9562 करोड रुपये के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये है। गैर–निवासी भारतीय मूल के लोगों के आधारभूत संरचना संबंधी क्रियाओं जैसे भवन, राजमार्गों का निर्माण आदि में निवेश की अनुमति दी गयी है। भारतीय यू.टी.आई. द्वारा न्यू इंडिया मिलेनियम स्कीम चालू की गयी है ताकि अनिवासी भारतीय डीलर में अंशदान करें। एस.बी.आई. द्वारा अनिवासी भारतीयों द्वारा अंशदान देने हेतु विदेशी मुद्रा के मूल्य में एक नया Resurgent India Bond प्रारम्भ किया गया है।

वित्तीय व बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

- बैकिंग क्षेत्र में विदेशी बैंकों की स्थापना की छूट दी गई है, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व, कुशलता का मार्ग होगा।
- बैंकिंग कम्पनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2003–04 के बजट में 74 प्रतिशत कर दिया गया है।
- बीमा नियमन व विकास अधिनियम आई डी.आर.ए. दिसम्बर 1999 में पारित किया गया। इस अधिनियम में घरेलू बीमा कम्पनियों में विदेशी पूँजी की अधिकतम सीमा कुल प्रदत्त पूँजी की 26 प्रतिशत निर्धारित की गई है। 2004–05 के बजट प्रस्तावों में इसे बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है।

विदेशी व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक सुधार

- स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र देश के कस्टम क्षेत्र के बाहर माने जायेंगे।
- फेरा के स्थान पर फेमा (Foreign Exchnge Management Act) बनाया गया है।
- भारतीय रुपये का अवमूल्यन 18 जुलाई 1991 में दो चरणों में किया गया ताकि निर्यात बढ़ाने में मदद मिले।
- आयात मंहगे हो जायें, जिससे विदेशी व्यापार के घाटे में कमी आ सके।

- पूँजीगत सामान तथा औद्योगिक कच्चे माल के रूप में काम आने वाले सामान के आयात पर प्रतिबन्ध हटाये गये है ताकि औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।
- भारतीय कम्पनियों को ASR/GDR बाजारों से साधन जुटाने की अधिक स्वतन्त्रता दी है।
- आयात शुल्कों में निरन्तर कटौती की गई ताकि पूँजीगत सामान व औद्योगिक कच्चे माल के सस्ते आयात से उनकी लागत में कमी व भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि हो।
- MRTP एक्ट को खत्म कर नया प्रतिस्पर्धात्मक अधिनियम 2002 लागू कर दिया गया है।
- अब 2004–09 को नई आयात–निर्यात नीति घोषित की गयी है। उच्च संरक्षणात्मक कस्टम डयूटी को 45 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।
- व्यापार खाते में रुपये की एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1993–94 में लागू गयी ताकि हवाला बाजार में विदेशी विनिमय पर प्रीमियम घटे व निर्यात बढ़े। 1994–95 में इसे चालू खाते में लागू कर दिया गया ताकि यात्रा शिक्षा व दवाओं आदि के क्षेत्र से प्रतिबन्ध हटे।
- निर्यात नियन्त्रणों में काफी उदारता प्रदान की गयी है।
- आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबन्धों में छूट और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए आयात निर्यात नीति में विशेष व्यवस्था की गयी है।
- निर्यातों पर भी मात्रात्मक प्रतिबन्धों की समाप्ति की गई। भारत सरकार ने 31 मार्च 2002 को एक नई पंचवर्षीय आयात नीति (2002–2007) द्वारा निर्यातों पर कुछ वस्तुओं को छोड़कर मात्रात्मक प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये।

राजकोषीय नीति व कर क्षेत्र में सुधार

- विदेशी कम्पनियों व उनकी शाखाओं पर आयकर की दर 65 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दी गई है व सरचार्ज हटा दिया गया है।
- निर्यात से प्राप्त लाभ को करमुक्त कर दिया है।
- निर्यात एन्टरटेनमेन्ट उद्योग को भी 80 HHC का लाभ दिया गया है।
- गैर कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क की उच्चतम सीमा 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दी गयी है।
- सीमा शुल्क में कटौती की गयी है।
- कई क्षेत्रों में आयात शुल्क की 300 प्रतिशत तक की ऊँची दरों को कई चरणों में घटाकर कई मामलों में 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
- यही नहीं पूँजीगत सामान पर आयात कर की दरों को 85 प्रतिशत से घटाकर 25 से 20 प्रतिशत कर दिया है। दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई हैं।

परिवहन व संचार क्षेत्र में सुधार

- शिपिंग इन्टरनेट कूरियर एयरपोर्ट क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गयी है।
- एयर ट्रांसपोर्ट घरेलू विमान सेवाओं में निवेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा 49 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि अनिवासी भारतीयों के लिए इसकी निवेश सीमा 100 प्रतिशत कर दी गई है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा में वद्धि

2004–05 के बजट प्रस्तावों में 8 जुलाई 2004 को दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत, बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। इससे इन क्षेत्रों में FDI (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) को बढ़ावा मिलेगा।

पूँजी बाजार में आर्थिक सुधार

भारतीय पूँजी बाजार में समुचित व पर्याप्त विकास के लिए कई आर्थिक सुधार लागू किये गये हैं। 1992 में SEBI की स्थापना और उसे पूँजी बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार मिल गया है। 1947 के पूँजी निर्गम नियंत्रण अधिनियम को परिवर्तित कर कन्ट्रोलर ऑफ केपिटल इस्यूज कार्यालय को समाप्त कर दिया तथा सेबी के अनुमोदन के बाद कम्पनियों को पूँजी बाजार में प्रवेश की छूट मिल गयी है। सेबी के साथ पंजीकरण कराने पर विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय पूँजी बाजार में निवेश की छूट दे दी गई है, फलतः 1995 तक 337 संस्थागत निवेशकों का पंजीकरण हुआ। भारतीय कम्पनियों को यूरो इक्विटी अंशों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों में प्रवेश की छूट मिल गयी। 1991 से 2000 तक दस वर्षों की अवधि में आर्थिक सुधारों को प्रथम पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के नाम से जाना जाता है, तत्पश्चात् आर्थिक सुधारों की दूसरी पीढ़ी प्रारम्भ होती है।

निष्कर्ष

भारत के आर्थिक सुधारों ने समस्त विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आर्थिक सुधारों अन्तर्गत किये गये वैश्वीकरण के कारण जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों के उद्योगपति व व्यवसायी, भारत में पूँजी विनियोजन में अधिक रूचि दर्शाने लगे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, में विश्व समुदाय का विश्वास बढ़ा है व विश्वास किया जा रहा है कि भारत निकट भविष्य में एक बाजार के रूप में उभरेगा तथा उसमें विश्व की महान आर्थिक शक्ति बनने की क्षमता है। आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप हुए वैश्वीकरण के कारण विश्व व्यावसायिक जगत में भारत की खोयी हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने में सफलता मिली है। निर्यात संवर्द्धन, आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन, विदेशी प्रत्यक्ष निजी विनियोगों व संस्थागत विनियोगों के संवर्द्धन की नई दिशाएँ उत्पन्न हुई हैं, जिनका प्रयोग राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. गर्ग, एच.एस. : आर्थिक भूगोल, राजेश पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2021।
2. भार्गव, नरेशः वैश्वीकरणः समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, रावत बुक्स, जयपुर, 2014।
3. जे.पी. एच पैनल ऑफ एक्सपर्ट : वैश्वीकरण तथा पर्यावरण, गुलीबाबा पब्लिशिंग हाउस, 2012।
4. दाधीच, नरेश, समसामयिक राजनीतिक सिद्धान्त, जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स्, 2015।
5. गुप्ता, रूपक दत्तः ग्लोबल पॉलिटिक्स, प्रथम संस्करण, पियर्शन इण्डिया, 2019।
6. जैन एवं माथुर : आधुनिक विश्व का इतिहास, 2010।
7. दत्त एवं सुन्दरम् (एस0 चन्द): भारतीय अर्थव्यवस्था, 2016।
8. लक्ष्मीनारायण नाथूराम का भारतीय
9. जैन विमल कुमार, नैगी के.एस., जैन आर. के., अर्थव्यवस्था आर्थिक नियोजन के सिद्धान्त व भारत में आर्थिक नियोजन।
10. ए. एन. अग्रवाल भारतीय अर्थव्यवस्था विकास एवं आयोजन।
11. ओझा बी. एल., भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्र पुरी भारतीय अर्थव्यवस्था।
12. शर्मा ब्रजकिशोर्र, शर्मा शैलबाला, –समसामयिक भारत।
13. अनिल गुप्ता, डॉ. एच. के. शर्मा, विनोद टेकचन्दानी, इरशाद– मानव अधिकार एवं कर्त्तव्य।
14. अमर उजाला।
15. टाइम्स ऑफ इण्डिया।

––==00==––